मलयेशिया 44,000 टन चीनी खरीदने को तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। चीनी निर्यात की संभावनाएं तलाश रही केंद्र सरकार को सफलता मिल रही है। मलयेशिया 44,000 टन चीनी भारत से खरीदने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल, सरकार ने गन्ना किसानों के बढ़ते बकाये के भुगतान के मद्देनजर चीनी निर्यात करने जैसा कदम उठाया है। निर्यात की संभावनाएं तलाशने के लिए सरकार द्वारा कई टीमें चीन, मलयेशिया और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों में भेजी गई थीं। जानकारी के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी चीनी खरीदने को तैयार हैं, इसलिए एक टीम जल्द ही एक बार फिर इंडोनेशिया होगी।

सरकार 15 लाख टन चीनी निर्यात के लिए करार कर चुकी है। उसे सितंबर तक 50 लाख टन निर्यात की उम्मीद है। इससे मिलों को सहायता मिलेगी, जिससे वे किसानों का बकाया चुका सकेंगे। मिलों पर किसानों का बकाया 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। सरकार ने बकाया चुकाने को 2018 में कई कदम उठाए थे। एक चौथाई बकाया रह गया था, जो अब बढ़ रहा है।

चीनी निर्यात की संभावनाएं तलाश रही सरकार को मिली सफलता

15 लाख टन चीनी निर्यात करने को सरकार कर चुकी है करार

50 लाख टन चीनी निर्यात सितंबर तक करने की उम्मीद

इसलिए सरकार ने उठाया कदम

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलें गन्ना किसानों का बकाया नहीं चुका पा रही हैं, जबकि सरकार ने बकाया चुकाने को बफर स्टॉक पर सब्सिडी देने के लिए निर्यात की अनिवार्य शर्त रखी है। लेकिन मिलों द्वारा निर्यात को लेकर प्रयास नहीं किए गए। इससे सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है।

न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग : उत्तर प्रदेश से हाल ही में गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के पास आई है। राज्य सरकार का कहना है कि न्यूनतम मूल्य को 29 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये कर दिया जाना चाहिए।

Amar Ujala
9/2/2019